POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 04 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! देश में 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दलों की शतरंज की बिसात बिछ चुकी हैं। सभी अपनी जीत की उम्मीद पाले अपने घोड़े दौड़ा रहें हैं। हाथी और ऊंट भी अपनी चाल से एक दूसरे को पटकनी देने को आतुर हैं।

राज्यों में मौका परस्ती क्षेत्रीय दल भी अपनी ओर से जोर अजमाने में पीछे नहीं हैं। बिसात पर सजी बाजी काफी महत्वपूर्ण है। परिणाम भी अचम्भित करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि, फैसला जनता-जनार्दन पर निर्भर है।

इधर जनता-जनार्दन द्वारा पिछले 67 सालों में विभिन्न दलों द्वारा देश को पहुंचाए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा हैं। राजनेताओं की निर्णयहीनता, उनके द्वारा काटी गई भ्रष्टाचार की फसल, की गई घोषणाएं व झूठे वादे, सिर्फ जीतने के मकसद बनाई दागी व भ्रष्ट प्रत्याशियों की फौज एवं जातीय व वंशवाद के समीकरणों से कितनी क्षति देश व नागरिकों को हुई हैं, इनका हिसाब-किताब भी आमजन को करना है।

देश में काफी लम्बे समय से किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया। इस बार भी सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ की कवायद शुरू हो गई है। गठबन्धन की इस राजनीति के दुष्परिणाम और पिछले सालों में घटित घटनाक्रम भी आमजन के सामने हैं।

खास यह है कि इस बार मतदाता शिक्षित और जागरूक है। मद्देनजर अहसास यह भी हो रहा है कि इस बार मतदाता किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता की चाबी उसके हाथ में रख दे ..... ।

सालाना एक लाख की आय तो भी मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

- राज्य सरकार अब सालाना एक लाख रुपए तक की आय वालों को भी मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। पहले यह सीमा 50 हजार रुपए थी। इसके लिए सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों में संशोधन कर दिया है। यह आय सीमा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 (एच) के तहत बढ़ाई गई है।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बेगार मांगने वाले या मानव तस्करी के शिकार, जातीय प्रताड़ना या हिंसा, प्राकृतिक आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, बंदी एवं मनोरोग के शिकार व्यक्तियों को भी मुफ्त विधिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विवाह सम्बन्धी व दहेज विरोधी कानून, अपहरण, बलात्कार तथा भरण-पोषण भत्ता पाने के मामलों आदि में आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होती। उन्हें अधिक आमदनी होने पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में उनके वकील की फीस, कोर्ट फीस, गवाह खर्च, आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाए जाते हैं।

रोडवेज व ठेकेदार को पार्किंग शुल्क ज्यादा वसूलना भारी पड़ा

जयपुर स्थित रामगंज बाजार निवासी रामजी लाल सोनी ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक और पार्किंग देकेदार के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि वह 10 जून, 2012 को अपने रिश्तेदार से मिलने सिंधी कैंप बस स्टैंड गया था। पार्किंग ठेकेदार ने उससे पार्किंग शुल्क 5 रुपए की जगह 10 रुपए मांगे। जब उन्होंने ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायत प्रबंधक से करने की बात की तो उसने उनकी व उनकी मां से बदसलूकी की। उन्होंने मजबूरन दस रुपए पार्किंग शुल्क दिया। इसकी शिकायत भी रोडवेज प्रशासन से की गई लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच का सहारा लिया ।

मामले की सुनवाई में उपभोक्ता मंच ने इसे सेवा दोष माना। मंच ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक व पार्किंग ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि वह ज्यादा वसूले 5 रुपए पर 10 जून, 2012 से बारह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता रामजी लाल सोनी को वापस करे और साथ ही 6500 रुपए हर्जाना भी अदा करें।

प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी सबसे आगे

जयपुर, 11 मार्च, 2014, विधानसभा चुनावों का अनुसरण करते हुए लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान से बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। प्रदेश के 76 फीसदी लोगों ने इस पर अपनी मुहर लगाई है, वहीं 67 फीसदी लोग प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के नरेन्द्र मोदी को ही पसन्द करते हैं। यह तथ्य कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) द्वारा हाल ही राजस्थान में कराए गए 'हालात सर्वे 2014' से सामने आया है। हालांकि प्रदेश के 66 फीसदी लोग यह मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के उदय से राजनीति की दशा व दिशा में परिवर्तन आएगा अर्थात राजनीति व्यक्तिवाद से हट कर मुद्दों पर आधारित होने लगेगी।

यह सर्वेक्षण लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव व तदोपरान्त की स्थिति के आकलन व लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से राज्य के विभिन्न जिलों में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कार्यरत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया।

संस्था द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व भी एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 64 फीसदी लोगों ने मोदी को पीएम पद के लिए पंसद किया था। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कराए गए नए सर्वेक्षण में तीन फीसदी अधिक लोगों की मोदी के प्रति आस्था बढ़ी है। राजस्थान के केवल 10 फीसदी लोगों ने आम आदमी पार्टी व इतने ही फीसदी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताई है। सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए मात्र 16 फीसदी लोगों ने अरविन्द केजरीवाल तथा 10 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पसन्द किया है।

लोकसभा चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी का असर राजस्थान में उतना नहीं है, फिर भी जितना है, उससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। प्रदेश के 62 फीसदी लोगों ने यह संभावना व्यक्त की है। प्रदेश के 47 फीसदी लोगों ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश को सही ठहराया है, जबकि इतने ही फीसदी लोग इसे सही नहीं मानते।

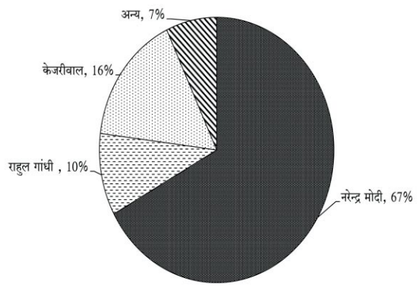

यह भी आया सामने

- *दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई, जिसे प्रदेश के 53 फीसदी लोगों ने सही नही माना, वहीं 72 फीसदी लोगों का कहना यह भी था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सहयोग से सरकार नहीं चला पाएगी। (यह सर्वे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व करवाया गया था)*
- *दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा पानी बिजली की दरों में की गई कमी और छूट को राजस्थान के 68 फीसदी लोगों ने उचित बताया।*

जनता से न करें झूठे वादे

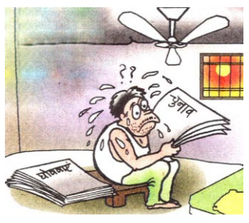

चुनाव से पहले अक्सर सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को बरगला कर अपने लिए वोट की भीख मांगती हैं। इनमें कई वादे तो ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं होता। अभी तक कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि इन लोकलुभावने वादों पर अंकुश लगाया जा सके।

हालांकि राजनीतिक दलों के ऐसे वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि चुनाव के दौरान किए गए जाने वाले वादे और प्रलोभन साफ और स्वच्छ चुनाव में बाधक है। यह वोटर को प्रभावित करते हैं। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश भी दिया था कि चुनाव घोषणा पत्र को चुनाव आचार संहिता में शामिल किया जाएं।

नहीं महकी किसानों की बगिया

पैसा होने के बावजूद उद्यान निदेशालय के अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते राष्ट्रीय बागवानी मिशन में तय लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं हुआ। नतीजतन, सरकारी राशि होते हुए भी किसानों की बगिया ढंग से महक नहीं सकी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन सरकार पिछले नौ माह में केवल 21 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में फल, सब्जी, मसाला, फूल, औषधीय पौधे लगाने, मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों के लिए किसानों को सहायता मिलती है। लापरवाही के चलते किसानों को यह सहायता नहीं मिल पाई।

नरेगा रोजगार दिवसों में आई गिरावट

मनरेगा में परिवारों को रोजगार मिलने के दिन लगातार घट रहे हैं। वर्ष 2013-14 के फरवरी माह तक के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार रोजगार दिवस 39 ही रह गए हैं। जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा 52 का था।

योजना के तहत होने वाले कार्यों में इस साल हर सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। महिलाओं के कार्यदिवस का मामला हो या फिर 100 दिन कार्य पूरा करने वाले परिवारों की बात हो, यह आंकड़ा पिछले चार सालों में लगातार गिरता जा रहा है। पंचायतें भी राशि खर्च करने के मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही।

खाद्य सुरक्षा योजना में घालमेल

विधान सभा चुनाव से पहले लागू की गई खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के पांच जिलों में आबादी से भी ज्यादा लोग चयनित कर दिए गए। इन जिलों में 84 लाख लोगों के नाम योजना में ज्यादा जोड़े गए हैं। अपात्र लोगों का भी इसमें चयन हो गया। हाल ही योजना की समीक्षा में यह गड़बड़ी सामने आई है।

दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, बांरा और सवाई माधोपुर जिलों में यह गड़बड़ी सामने आई है। जल्दबाजी में तैयार की गई कई सूचियों में जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चयनित लोगों की वास्तविकता का पता लगाया जाएगा और जरूरतमंदों के नए सिरे से नाम भी जोड़े जाएंगे।

सरकार रखेगी अनाज का हिसाब

अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश की सरकार खलिहान से मंडी और गोदामों तक पहुंच रही फसलों एवं उत्पादन पर नजर रखेगी। किसानों के खलिहानों में व ट्रांसपोर्टेशन के समय अनाज के खराब होने, चूहों के खाने, किसान के स्वयं के उपयोग और बीज के लिए रखने से लेकर पशुओं को खिलाने, खलिहान से सीधे मंडी में बेचने तक की जानकारी सरकार अपने पास रखेगी।

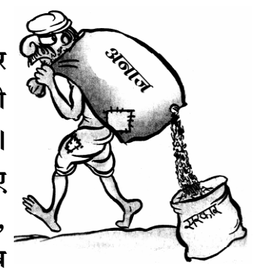

इसके लिए सरकार किसानों से भी जानकारी लेगी। फिलहाल इसके लिए चार जिले सीकर, जोधपुर, भरतपुर व चित्तौड़गढ़ का चयन किया गया है। इन जिलों के 20-20 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में इसके लिए सर्वे किया जाएगा।

महिला आरक्षण में पुरुष बाधक

राज्यपाल मार्ग्रेट आल्वा का मानना है कि राजनीति में महिलाओं के आरक्षण में रुकावट के लिए राजनीतिक दल नहीं, बल्कि पुरुष नेता सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। राजनीति में पुरुष अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी चूंकि राज्य सभा में बिल आ गया है, इससे उम्मीद बंधी है। महिला दिवस पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ज्यादा महिलाएं चुनाव में जीत कर आएंगी।

उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं ने अब तक कई संघर्ष किए हैं। संतोष की बात यह है कि अब पुरुषों की सोच भी बदल रही है।

राजनीति छोड़े 'आप'

'आम आदमी पार्टी को यदि समाज व देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो राजनीति का मार्ग छोड़कर समाज सुधार का कार्य कर जागरूकता लानी चाहिए व भ्रष्टाचार के खिलाफ पैरवी करनी चाहिए।' मुरलीधर शर्मा, टोंक

बहुत कीमती है वोट

देश में इस बार लोकसभा चुनाव काफी रोचक हैं। पिछले कुछ सालों के राजनीतिक घटनाक्रमों ने मतदाताओं को काफी जागरूक कर दिया है। वह अब अपने वोट की ताकत को समझने लगे हैं।

कुछ ही महीनों पहले हुए विधान सभा चुनावों के परिणामों ने सभी को चौंका दिया था। जनता के सामने दो खास मुद्दे हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा महंगाई। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी है। जनता उसे वोट देना पसंद कर रही है जो इन समस्याओं को दूर करने और अपने स्वार्थ के बजाय देश के विकास को अहमियत देगा। - अजय सारस्वत, जयपुर

उपभोक्ता जन संवाद आयोजित

'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर 'फिक्स ऑवर फोन राइट्स' विषय पर जन संवाद आयोजित किया गया। संवाद के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से सिम खोने पर एफआईआर दर्ज कराने की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई।

कार्यक्रम में कट्स निदेशक जार्ज चेरियन ने सेवा प्रदाता कंपनियों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया कि मोबाइल फोन आज आम आदमी की जरूरत बन गया है। इसके माध्यम से बैंकिग सेवाएं, ई-कामर्स या सामाजिक सेवाओं का जुड़ाव भी होने लगा है। जन संवाद में सेवा प्रदाताओं जिनमें खास तौर पर बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, आईडिया आदि के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने अपनी कंपनियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं, शर्तों, नियमों एवं उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मोबाइल सेवाओं से सम्बन्धित आम उपभोक्ता की विभिन्न समस्याओं को उठाया और पूरे देश में फ्री रोमिंग की मांग भी की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर